<u>पंचायती राज मंत्रालय</u>

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) की <u>दिसम्बर, 2018</u> माहकी प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सारांश

1. भारत-गंगा के मैदानों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में जीपीडीपी के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन/कायाकल्प पर लखनऊ में दिनांक 7-8 दिसंबर 2018 के दौरान सहित एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इन छह राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा, मंत्रालयों/संस्थानों के प्रतिनिधि सहित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय; राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद; जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय केंद्र, गाजियाबाद; आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर; सीएसआईआर-केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान, लखनऊ; आईसीएआर-भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, यूपी; आईसीएआर- बकरी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान मथुरा; नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), केवीआईसी, लखनऊ कार्यालय; कुदुम्बश्री - एनआरओ; यूनिसेफ - भारत और संयुक्त राष्ट्र महिलाओं ने कार्यशाला के विचार-विमर्श में भाग लिया। कार्यशाला के विचार-विमर्श छह राज्यों में तैयार किए जा रहे जीपीडीपी की गुणवत्ता में सुधार के लिए दूरगामी परिणाम देंगे।

2. गोवा में (4 -5 दिसंबर 2018), नागालैंड (6-7 दिसंबर 2018), मेघालय (17 दिसंबर 2018) और मध्य प्रदेश (24 दिसंबर 2018) में जीपीडीपी को अच्छी गुणवत्ता में तैयार करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्लानप्लस पर प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन विशेष उपाय के रूप में किया गया था।

3. मंत्रालय ने 21-22 दिसंबर, 2018 को केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (किला) त्रिशूर, केरल में ग्राम पंचायत विकास योजना पर आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का भी समर्थन किया। कार्यशाला से दक्षिणी राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने में मदद मिलेगी।.

4. जहां भी आवश्यक हो, पीपुल्स प्लान कैंपेन- 'सबकी योजना सबका विकास' की प्रभावी भूमिका के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं, जिसके तहत अगले वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपीज़) तैयार करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2018 के दौरान संरचित ग्राम सभा की बैठकें

आयोजित की गई हैं। संबंधित हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अभियान की गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की दूसरी बैठक 5 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में 11 राज्यों बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार किया गया।

6. 10 राज्यों को दिसंबर, 2018 के महीने में 97.25 करोड़ रुपये के फंड जारी किए गए, जिनकी वार्षिक कार्य योजनाओं को सीईसी की पहली और दूसरी बैठक के दौरान मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, 2.33 करोड़ रुपये के फंड को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद को आरजीएसए के तहत विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी किया गया।

7. महीने के दौरान, एमओपीआर ने वर्ष 2016-17 के लिए जम्मू और कश्मीर को 407.62 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की पहली और दूसरी किस्त, वर्ष 2018-19 के लिए बिहार को 2099.855 करोड़ रुपये, हरियाणा को 387.995 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 920.77 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 1354.39 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 3574.37 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 1370.344 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को सिफारिश की है।

8. महीने के दौरान, वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 180.815 करोड़ रुपये, गुजरात को 862.68 करोड़ रुपये और सिक्किम को 14.835 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किस्त वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी किया है।

9. वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत मूल अनुदान की कुल निर्मुक्ति 29942.87 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले 28600.45 करोड़ रुपये है, वर्ष 2017-18 के दौरान 34596.26 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में 32157 करोड़ रुपये है और यह वर्ष 2018-19 के लिए 40021.63 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में 20227.24 करोड़ रुपये है। वर्ष 2016-17 के लिए 3927.65 करोड़ रुपये आवंटन के एवज में कार्य निष्पादन अनुदान का आवंटन 3499.45 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रुपये के आवंटन के एवज में 1106.90 करोड़ रुपये है।

10. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, एमओपीआर सख्ती से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों पर जोर दे रहा है। इस संबंध में, जीपी/वेंडर

पंजीकरण के लिए प्रियासॉफ्ट 2017-18 पर खाता बंद करने के लिए राज्यों के साथ मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस करता रहा है। वर्ष 2017-18 के लिए, 91% ग्राम पंचायतों ने अपने खाते की किताबें बंद कर दी हैं और 2,27,074 ग्राम पंचायतें पीएफएमएस पर पंजीकृत किए गए हैं जबकि शेष ग्राम पंचायतें उसी की प्रक्रिया में हैं। लगभग 89,824 ग्राम पंचायतें ने पहले ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र खरीद लिए हैं।

11. ई-फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और एसेट्स की जियो-टैगिंग पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करते हुए, 04 से 08 दिसंबर, 2018 तक गोवा में पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) एप्लीकेशन पर पांच दिवसीय आवासीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

12. पंचायत पुरस्कार -2019 (मूल्यांकन वर्ष 2017-18) के लिए पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना के अंतर्गत, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी), नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी) और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) अवार्ड की श्रेणियों के तहत ऑनलाइन नामांकन (ग्राम पंचायत विकास योजना) राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों से आमंत्रित किये गये हैं। 31.12.2018 को, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों ने अपने ऑनलाइन नामांकनों को बंद कर दिया है। ये नामांकन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सत्यापन की प्रक्रिया के अधीन हैं।

Ministry panchayati Raj

Summary on Major achievements, significant developments and Important events of MoPR for the month of December, 2018

1. A Workshop on Economic and Social Transformation through GPDP for States in Indo-Gangetic plains (Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and West Bengal) was organised at Lucknow during 7th -8th December 2018. Apart from representatives from these six States, delegates from Ministries/Institutions including Ministry of Agriculture & Farmers Welfare; Ministry of Environment, Forests and Climate Change; Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; National Institute of Agricultural Extension Management, Hyderabad; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; ICAR- Indian Institute of Pulses Research Kanpur; CSIR- Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants), Lucknow; ICAR-Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, UP; ICAR-Central Institute for Research on Goats, Mathura; National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED), KVIC, Lucknow Office; Kudumbashree-NRO; UNICEF – India and UN Women participated in the deliberation of the Workshop. The deliberation of the Workshop would go a long way in improving quality of the Gram Panchayat Development Plan (GPDP) being prepared in the six States.

2. Training/Workshop on PlanPlus was organised in Goa (4th -5th December 2018), Nagaland (6th-7th December 2018), Meghalaya (17th December 2018) and Madhya Pradesh (24th December 2018) as special measure for providing support to the States for preparing the GPDP in good quality.

3. Ministry also supported Southern Regional Consultation Workshop in Gram GPDP organised at Kerala Institute of Local Administration (KILA) Thrissur, Kerala on 21-22 December, 2018. Workshop would help in preparation of GPDP in Southern States viz. Andhra Pradesh, Telangana, Tamilnadu, Karnataka and Kerala.

4. Regular follow-up actions and interventions have been initiated, wherever required, for effective roll out of the People's Plan Campaign- 'Sabki Yojana Sabka Vikas' under which structured Gram Sabha meetings have been held during 2nd October to 31st December, 2018 for preparing GPDPs for the next financial year 2019-20. The activities of the Campaign are being monitored regularly through Video Conferences with the concerned stakeholders.

5. The second meeting of Central Empowered Committee (CEC) of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) was held on 5th December, 2018 at New Delhi. In the meeting, the Annual Action Plans of 11 States viz. Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Odisha, Punjab, Uttrakhand and 3 Union Territories viz. Andaman and Nicobar Islands, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu were considered

. .

6. Funds to the tune of Rs. 97.25 Crores were released to 10 States in the month of December, 2018 whose Annual Action Plans were approved during the first and second meeting of CEC. Further, funds to the tune of Rs. 2.33 crores were released to National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR), Hyderabad towards different approved projects under RGSA.

7. During the month, MoPR has recommended to Ministry of Finance (MoF) for release of 1st and 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 407.62 crore to Jammu & Kashmir for 2016-17, 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 2099.855 crore to Bihar, Rs. 387.995 crore to Haryana, Rs. 920.77 crore to Karnataka, Rs. 1354.39 crore to Madhya Pradesh, Rs. 3574.37 crore to Uttar Pradesh and Rs. 1370.344 crore to West Bengal for 2018-19.

8. During the month, MoF has released 2nd instalment of Basic Grant of Rs. 180.815 crore to Himachal Pradesh, Rs. 862.68 crore to Gujarat and Rs. 14.835 crore to Sikkim for FY 2018-19.

9. The total release of Basic grant under FFC for the year 2016-17 is Rs. 28600.45 crore against the allocation of Rs. 29942.87 crore, during 2017-18 is Rs. 32157 crore against the allocation of Rs. 34596.26 crore and it is Rs. 20227.24 crore against the allocation of Rs.40021.63 crore for the year 2018-19. Release of Performance Grant is Rs. 3499.45 crore against the allocation of Rs. 3927.65 crore for 2016-17 and Rs. 1106.90 crore against allocation of Rs. 4444.71 crore, for the year 2017-18.

10. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of Public Financial Management System (PFMS). In this regard, the Ministry has been conducting video conferences; pursuing the States for closure of account on PRIASoft for 2017-18, GP/vendor registration. For the year 2017-18, 91% of the Gram Panchayats have closed their account books and 2, 27,074 GPs have been registered on PFMS while remaining GPs are in the process of the same. Around 89,824 GPs have already procured Digital Signature Certificates.

11. A five day residential workshop cum training was held at Goa on Panchayat Enterprise Suite (PES) Applications during 4th to 8th December, 2018 focusing mainly on e-Financial Management System, Public Financial Management System and Geo-tagging of assets.

12. For Panchayat Awards-2019 (Appraisal Year 2017-18) under the Incentivization of Panchayats Scheme, online nominations under the categories of Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP), Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar (NDRGGSP) and GPDP Award have been invited from State Governments/Union Territory (UT) Administrations. As on 31.12.2018, Panchayats in 25 States/UTs have freezed their online nominations. These nominations are under verification in the respective States/UTs.

****